

माधोपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि आदेश दिनांक - 04/11/2022

अरविन्द कुमार बन्नाम सरकार
अपील संख्या 16/2022

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राजग)

पीदासीन अधिकारी :- हरि राम सोन्या, आर.ए.एस.

अपील संख्या-16/2022

(223 आर.टी.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. संख्या-2022/10

उत्तरवाच

1. अरविन्द कुमार पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जैन भादीवाल प्रो. महेश दर्शक
निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज.

अपीलाष्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।
मुख्य रेसपोडेन्ट/दादी
2. बदी प्रसाद पुत्रान दुर्गालाल महाजन निवासी गंगापुर सिटी
3. रामस्वरुप पुत्र दुर्गालाल (फौत)
 - 3/1. रमेश चन्द पुत्र रामस्वरुप
 - 3/2. गुलाब चन्द पुत्र रामस्वरुप (फौत)
 - 3/2/1. अशोक पुत्र गुलाब चन्द
 - 3/2/2. सुनील पुत्र गुलाब चन्द
 - 3/2/3. अनिल पुत्र गुलाब चन्द
 - 3/3. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरुप
 - 3/4. महेश चन्द पुत्र रामस्वरुप
 - 3/5. श्याम लाल पुत्र रामस्वरुप
 - 3/6. बाबूलाल पुत्र रामस्वरुप
4. हरिचरण पुत्र दुर्गालाल (फौत) जाति महाजन
 - 4/1. जगदीश पुत्र हरिचरण
 - 4/2. चन्द्रशेखर पुत्र हरिचरण
 - 4/3. सतीश चन्द पुत्र हरिचरण
 - 4/4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिचरण
5. घुडमल पुत्र गेदी लाल महाजन (फौत)
 - 5/1. गोविन्द पुत्र घुडमल (फौत)
 - 5/1/1. सुरेश पुत्र गोविन्द



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



अरविन्द कुमार बनाम सरकार
अपील संख्या 16/2022

- 5/1/2. नरेन्द्र पुत्र गोविन्द (फौत)
5/1/2/1. नमन पुत्र नरेन्द्र
5/1/3. राजेश पुत्र गोविन्द
5/1/4. रघुनन्दन पुत्र गोविन्द
5/1/5. मुकेश पुत्र गोविन्द
6. श्रीमती जया देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा (फौत)
6/1. ओमप्रकाश शर्मा उर्फ पप्पू जाति ब्राह्मण
समस्त निवासीयान गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

-तरतीबी रैसपोडेण्ट/प्रतिवादीगण



उपस्थित:-
श्री श्याम मोहन शर्मा अभिभाषक अपीलांत,
पैरोकार सरकार अभिभाषक रैसपोडेण्ट संख्या 1,
रैसपोडेण्ट 2 ता 6/1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं,

∴ निर्णय ∴

दिनांक:- 04.11.2022

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपांड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 109/2001 वउनवान सरकार बनाम रामस्वरूप वगै में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मे एक वाद राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(लैण्ड हॉल्डर) गंगापुर सिटी द्वारा इस आशय का पत्र किया कि आराजी खसरा नंबर 463/630 रकवा 1.50 हैक्टेयर पूर्व में जेटमल हीरालाल नामक तेल मिल कार्यरत थी, जिसकी खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल रामस्वरूप, हरिचरणलाल, बंदीप्रसाद पि0 दुर्गालाल महाजन सा0देह 1/2 घूडमल पुत्र गेंदीलाल हि0 1/2 महाजन सा0 देह गंगापुर सिटी के नाम कस्बा गंगापुर सिटी में अंकित है। उक्त

82
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात पर प्रतिवादीगण ने आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग किया है, जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1965 के विपरीत है। खातेदारान को उक्त भूमि केवल औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिए दी गई थी जिसका आवंटित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कर भूमि का अवैध बेतान कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ कार्य किया है। इसलिफ् हाल प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात वाके माम गंगापूर सिटी से वेदखल किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार हाल रेशपोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मातहत अदालत से हाल तरतीवी रेशपोडेन्टस को आराजी खरारा नंबर 463/630 रकबा 1.50 हेक्टेयर स्थित माम गंगापूर सिटी से वेदखल किया जाकर भूमि राजस्थान राज्य सरकार को दिलाया जाने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1608 का पेश किया

अदालत मातहत द्वारा भूमि को आवंटन के प्रयोजन से विपरीत काम में लेने का मानते हुये, उक्त आलैच्य आदेश पारित करते हुये दिनांक 28.02.2005 को धारा 176, 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत संबंधित खातेदार (भूमि विक्रेता एवं क्रेता) को वेदखल कर भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाई चक दर्ज करने का आदेश पारित किया। इस निर्णय से व्यथित होकर हाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में गिगाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत के समक्ष रेशपोडेन्ट संख्या 1/वादी नें आराजीयात खरारा नंबर 463/630 रकबा 1.50 हेक्टेयर की भूमि का वास्तविक स्थिति के तथ्यो से विपरीत उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की है, वास्तविक स्थितिनुसार आराजीयात का साविक खरारा नं. 359 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा सम्वत् 2015 प्रथम सैटलमेन्ट मुताबिक पचा सैटलमेन्ट उक्त खरारा नम्बर एकीकरण के समय खरारा नम्बर 657, 658, 659 गिन 665, 666 गिन खरारा नम्बरो से बना हुआ है। प्रथम सैटलमेन्ट के समय उक्त भूमि का पचा हाल तरतीवी रेशपोडेन्टान के पूर्वज दुर्गालाल व मूलमल गिरारान गेदीलाल महाजन के नाम से जारी हुआ जो मलत रूप से जारी किया गया। चूकि साविक खरारा नम्बर 359 के रकबे में से 3554 वर्गमज क्षेत्रफल भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वज सैटलमेन्ट से पूर्व से काविज चले आ रहे है। उक्त भूमि पर आजादी से पूर्व जयपुर शिारत संवत् 2003(सन् 1946) खरारा गिरदावरी संवत् 2013 में उक्त खरारा नम्बरान् में कशीव 27 बिस्वा भूमि की किरम गैर मुगगिन शिनेगा दर्ज है। शिनेगा निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर मुलाब टाकिज बनाया गया जो कि वर्तमान में महेश टाकिज के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात् गंगापूर सिटी में वर्ष 1967 में टाउन इम्प्लुवमेन्ट ट्रस्ट का सर्वे हुआ जिसमें भी खरारा नम्बर 659, 662 लगायत 665 व 667 में भी किरम शिनेगा दर्ज है। उक्त शिनेगा हाउस के क्षेत्रफल 3554 वर्गमज की एतज में राज्य सरकार को समय समय पर लीज राशि व नजराना राशि जमा होती चली आ रही है।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

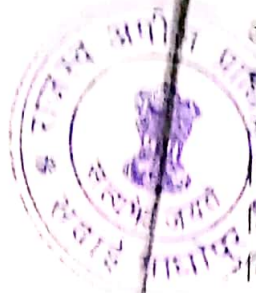
तथ्य-प्रतिलिपि

राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

माननीय सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 02.02.2017 से लीज एवं कतखत शर्तों समूह
नियमों के आवेग हुए। जो वर्ष 2014 तक लगे लीज व कतखत शर्तों अधिनियम द्वारा जमा
कतखत जोतल रिकॉर्ड करवाई गई है। इस प्रकार मातहत अपीलन में बिना समय खंडन एवं
अपीलांत की बिना मसखत बनाये वसा गीके व सरकारी रिकॉर्ड की मसखत करके सुने
वाल ऐसीजेन्ट संख्या 1/वादी ने मसखत की रिपोर्ट हुये मातहत अदालत के समक्ष मातहत
तथ्यों को उल्लेखित कर, दावा प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर मातहत अदालत ने
न्यायिक सिद्धांतों के विधीत जाकर आजीम्य आदेश पारित किया।

ऐसीजेन्ट संख्या 1 ने अपीलांत के 3554 वर्ग मज में निर्मित सिमेंटा हाउस की अतिक्रमि मानदे
हुए पारा 91 एल आर एक्ट मुकदमा संख्या 483/2005 वदमवान सरकार बनाम अतिक्रम
मुद्दार की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी जिसमें अपीलांत की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के
आधार पर 18.02.2009 को प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है।

अपीलांत द्वारा वर्ष 2011 में अदालत मातहत उपखण्ड मगापुर सिटी में एक वाद खस 88, 88
वा 91 अन्तर्गत राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया था कि
काश्तकी खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हेक्टेयर भूमि में से 3554 वर्गमज में निर्मित
सिमेंटा हाउस वादी की मालिकियत है जिसे सिवाईयक से हटाकर अतीलांत के नाम दर्ज
किया जावे। अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद 28.05.2013 को खारिज कर दिया गया। उक्त
निर्णय की अपील न्यायालय राजसव अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में पेश की गई जिसमें
अपील में निर्णय दिनांक 17.06.2013 को आदेश किए गए कि खसरा नम्बर 463/630 रकबा
1.50 हेक्टेयर में से 3554 वर्गमज भूमि में क्या महेश टाकिज के क्षेत्रफल को सिवाईयक से
हटाकर पृथक से बटा नम्बर कायम किया जावे व बटा नम्बर में महेश टाकिज अंकित किया
जाकर लीज शर्तों के मुताबिक कार्यवाही की जावे। माननीय राजसव मण्डल राजस्थान अजमेर
द्वारा 05.08.2015 को आदेश माननीय राजसव अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश को
रखावत रखा। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सिविल रिट विटिसन संख्या
17717/2015 के आदेश दिनांक 02.02.2017 के निर्णय में राजसव अपील प्राधिकारी व
माननीय राजसव मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को निरस्त कर दिया गया। डी वी
रोशल अपील रिट नम्बर 454/2017 जो अपीलांत द्वारा पेश की गई थी, जिसमें आदेश
दिनांक 04.05.2018 के अनुसार माननीय सिविल बेंच के आदेश को अदास्त करते हुए सुनवाई
हेतु माननीय सिंगल बेंच को लौटा दी गई। जो वर्तमान में विवादाधीन है। माननीय एस वी के
निर्णय में राणी विदुओ पर निर्णय पारित करते हुए मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 28.02.
2005 को अलग से चुनौती नहीं दिए जाने का तथ्य कानूनन उठाया गया।



राजसव अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

4
त्य-प्रतिलिपि

राजसव अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जिसकी जानकारी अपीलान्ट को माननीय एस वी के निर्णय पारित करने के पश्चात् हुई। इस कारण यह अपील पेश की जा रही है अदालत मातहत आलौच्य आदेश दिनांक 28.02.2005 के खसरा नम्बर 463/630 गंगापुर सिटी की भूमि का निर्णय समरी प्रोसेडिंग लिखा किया गया है। जिसमें न तो अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया न ही सुनावार्ई का मौका दिया गया। उक्त भूमि में से 3554 वर्गगज को भूमि नियमित वाद से अपीलान्ट स्वामित्व प्राप्त होने के कारण आलौच्य आदेश प्रभावहीन व शून्य हो गया है, इस कारण अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि (3554 वर्गगज) की हद तक निरस्त/निष्प्रभावी फरमाया जावे।

अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी साक्षी के आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि 3554 वर्गगज की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पों को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की वहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त वहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलान्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद विन्दु के बारे में नरम रुख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने लिखित वहस पेश की गई जिसमें अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

प्रकरण सरकार के द्वारा जवाब वहस में कथन किया गया कि प्रकरण अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ में निलम्बित है और खण्डपीठ के निर्देशानुसार सम्पत्ति प्रकरण निर्णय होना शेष है जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के

राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

द्वारा सिविल रिट पिटिसन के सम्बंध में जय तक कोई निर्णय नहीं हो तब तक किसी प्रकार का आदेश नहीं किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 28.02.2005 के द्वारा हित प्रभावित हो रहे हैं। अपीलांट को अदालत मातहत ने पक्षकार नहीं बनाया गया और सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। पार्थी का विवादग्रस्त भूमि के हित व अधिकार निहित है। इसलिए पार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की अपील संख्या 34/2013 बउनवान अरविन्द कुमार पल्लीवाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी निर्णय दिनांक 17.06.2013 में अपीलांट अरविन्द कुमार पल्लीवाल पुत्र गुलाब चन्द पल्लीवाल प्रो. महेश टाकिज गंगापुर सिटी अपीलांट के रूप में संशोधित है इस आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टैयर किस्म चाही प्रथम ग्राम गंगापुर जिला सवाई माधोपुर की जमाबंदी संवत् 2056-2059 रामस्वरूप, हरिचरणलाल, बद्रीप्रसाद, पिता दुर्गालाल महाजन सा. देह हिस्सा 1/2 घुड़मल पुत्र गेंदीलाल 1/2 हिस्सा महाजन सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी, संवत् ग्राम गंगापुर के खसरा नम्बर 463/630 में यह आराजीयात गैर मुमकिन आवादी के रूप में दर्ज है। पत्रावली में अपीलांट में अंकित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं है और न ही माननीय एकल पीठ व डी. बी. के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की अपील संख्या 34/2013 बउनवान अरविन्द कुमार पल्लीवाल पुत्र गुलाबचन्द पल्लीवाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी (अपील मुकदमा नम्बर 75/2011 निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.2013 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी) निर्णय दिनांक 17.06.2013 की एवं न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रार्थना पत्र संख्या 109/2001 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी बनाम रामस्वरूप, बद्री, घुड़मल वगैरहा अन्तर्गत धारा 175,177 निर्णय दिनांक 28.05.2005 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया।



62
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य अनुतोष यह है कि :-

"अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि (3554 वर्गगज) की हद तक निरस्त/निष्प्रभावी फरमाया जावे।"

यह अनुतोष न्यायालय हाजा के अपील संख्या 34/2013 निर्णय दिनांक 17.06.2013 में अपीलांट को इस अपील के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 द्वारा पूर्व में ही अनुतोष प्राप्त हो चुका है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 34/2013 एवम् प्रस्तुत अपील में पक्षकार एवं वाद की विषयवस्तु समान है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 34/2013 का ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगपुर सिटी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2013 मुकदमा नम्बर 75/11 निरस्त किये जाते हैं तथा आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टैयर स्थित ग्राम गंगपुर सिटी के 3554 वर्गगज क्षेत्रफल में बना महेश टाकीज वादी द्वारा निर्मित है को इस खसरा नम्बर 463/630 1.50 हैक्टैयर में से पृथक किया जाता है। तथा सिवायचक से हटाया जाकर पृथक से बटा नम्बर (3554 वर्गगज) के कोयम किये जावे। तथा उक्त बटा नम्बर को वादी महेश टाकीज मुताबिक कार्यवाही की जावे। एवं उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 मुकदमा नम्बर 109/01 अपीलांट के रकबे खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टैयर में से अपीलांट के विरुद्ध 3554 वर्गगज की हद तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप सिनेमा लीज राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।"

प्रस्तुत अपील अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगपुर सिटी के आदेश दिनांक 28.02.2005 के विरुद्ध पेश की गई है एवं जो अनुतोष चाहा गया है उसका उल्लेख उपर्युक्तानुसार है।

प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष को अपीलांट के पक्ष में पूर्व में ही न्याया हाजा के अपीलांट संख्या 34/2013 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.13 में निर्णित किया जा चुका है। जो इस प्रकार है

".....एवं उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 मुकदमा नम्बर 109/01 अपीलांट के रकबे खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टैयर में से अपीलांट के विरुद्ध 3554 वर्गगज की हद तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है.....।"

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

इस संबंध में पूर्व-न्याय धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू होते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

Explanation 1- The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष "अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 28.02.2005 को अपीलार्थी के हक में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में उल्लेखित भूमि (3554 वर्गगज) की हद तक निरस्त/निष्प्रभावी फरमाया जावे," अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 109/2001 दिनांक 28.02.2005 को भी, न्यायालय हाजा की अपील संख्या 34/2013 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2013 में ही विनिश्चित किया जा चुका है। निर्णय व डिक्री का आशिक भाग इस प्रकार है:- ".....एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पूर्व में प्रारित निर्णय दिनांक 28.02.2005 मुकदमा नम्बर 109/2001 अपीलांट के रकबे खसरा नम्बर 463/630 रकबा 1.50 हैक्टेयर में से अपीलांट के विरुद्ध 3554 वर्गगज की हद तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है.....।" उपर्युक्त कारण से प्रस्तुत अपील में धारा 11 (पूर्व-न्याय) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू होने के कारण, पूर्व में ही विनिश्चित अनुतोष को पुनः विनिश्चय करना कानूनी रूप से वाधित है। इस कारण पत्रावली को इत्ती स्तर पर दफ्तर दाखिल की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(हरि राम गुप्ता)
04.11.22
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर